नवोन्मेष
रुक्टा (राष्ट्रीय)

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)
(अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से संबद्ध)

website: www.ructarashtriya.org **Email:** info@ructarashtriya.org, ructarashtriya@gmail.com

केन्द्रीय कार्यालय : देराश्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर, जयपुर-302004
प्रधान कार्यालय : सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर-305001 (राज.)
अध्यक्ष : डॉ. दिग्विजयसिंह शेखावत, बीकानेर मो. 9414452369, 9983007575
महामंत्री : डॉ. नारायणलाल गुप्ता, अजमेर मो. 9414497042

परिपत्र क्रं. : रुक्टा (रा.)/2018-19/01 श्रावण कृ. १४ वि. स. २०७५ तदनुसार १० अगस्त, 2018
(सभी इकाई सचिवों एवं सक्रिय सदस्यों को समस्त सदस्यों में प्रसारित करने के अनुरोध सहित प्रेषित)

प्रिय बंधु/भगिनी,

सादर नमस्कार।

गत परिपत्र के पश्चात् मुख्यमंत्रीजी, उच्च शिक्षा मंत्रीजी एवं यू.जी.सी. अध्यक्ष से भेंट, नवीन यू.जी.सी. रेगुलेशन, शिक्षक सम्मान के आवेदन की जानकारी के साथ प्रदेश, राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं उच्च शिक्षा संवर्ग राष्ट्रीय कार्य-समिति की बैठक, प्रदेश चिंतन वर्ग के विवरण सहित अन्य सूचनाओं के साथ यह परिपत्र आपके समक्ष प्रस्तुत है -

शिक्षक समस्याओं के संबंध में संगठन की गतिविधियाँ एवं उपलब्धियाँ

1. **मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी से भेंट** - संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी एवं उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी जी से दिनांक 5 अगस्त 2018 को नाथद्वारा में भेंट की। संगठन की ओर से पदनाम परिवर्तन सहित उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों के हित में कदम उठाने तथा सातवें वेतन हेतु संगठन के पत्र पर कार्यवाही करने हेतु मुख्यमंत्रीजी का आभार व्यक्त किया गया। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि संगठन की भावना के अनुसार उन्होंने अधिकारियों को नवीन यू.जी.सी. वेतनमान हेतु अपेक्षित कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं तथा शीघ्र ही उच्च शिक्षा के शिक्षकों को नवीन वेतनमान मिल सकेगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों के लिए और उच्च शिक्षा के समग्र विकास के लिए संकल्पित है।

2. **नवीन यू.जी.सी. वेतनमान हेतु भेंट** - संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने 30 जुलाई 2018 को उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख शासन सचिव श्री तन्मय कुमार एवं संयुक्त सचिव श्री वी. एस. बाँकावत से विस्तृत भेंट कर विश्वविद्यालय एवम् महाविद्यालय शिक्षकों को नवीन यू.जी.सी. वेतनमान अविलंब देने की माँग की। संगठन महामंत्री ने उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी एवं श्री तन्मय कुमार को बताया कि केंद्र द्वारा यू.जी.सी. वेतनमान की घोषणा के साथ ही संगठन निरंतर सातवें वेतन आयोग के अनुरूप नवीन यू.जी.सी. वेतनमान का लाभ दिए जाने की माँग कर रहा है। राज्य के अधिकांश कर्मचारियों, अधिकारियों को नवीन वेतन आयोग का लाभ दिया जा चुका है, किंतु महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षक अभी भी इस लाभ से वंचित हैं। उच्च शिक्षा मंत्री और श्री तन्मय कुमार ने बताया कि संगठन के पत्र पर कार्यवाही करते हुए

विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों को नवीन यू.जी.सी. वेतनमान देने पर होने वाले वित्तीय भार की गणना करवा ली गई है तथा संगठन की भावनाओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया गया है व उनके निर्देश पर आगामी कार्यवाही चल रही है। उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी जी ने कहा कि वह स्वयं इस फाइल को ट्रैक कर रही हैं तथा मुख्यमंत्री जी के निरंतर संपर्क में हैं। शिक्षकों की भावनाओं के अनुसार शीघ्र ही सकारात्मक कार्यवाही करवाने का उनका प्रयास है।

3. **उच्च शिक्षा मंत्री जी से भेंट** – उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी जी के साथ शिक्षक समस्याओं के संबंध में संगठन के प्रतिनिधि मंडल की 18 मई 2018 व पुन: 30 जुलाई 2018 को लंबी भेंटवार्ता हुई। 18 मई को भेंटवार्ता में पे बैंड-4 के लिए पात्र शिक्षकों पर यू.जी.सी. नियम भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं करने पर सहमति बनी। सातवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है,यह बताते हुए मंत्री जी ने कहा कि इस संबंध में वित्तीय भार की गणना करवाने के पश्चात् फाइल को पुन: वित्त विभाग में भेजने के निर्देश दे दिए गए हैं। वह स्वयं मामले में रुचि लेकर इस विषय को देख रही हैं । राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्यों की कमी से उत्पन्न समस्याओं को विस्तार से मंत्री जी के ध्यान में लाया गया। आर.वी.आर.ई.एस. शिक्षकों के लंबित सी.ए.एस. मुद्दे पर अपेक्षित कार्यवाही करने, लोक सेवा आयोग के माध्यम से राजकीय महाविद्यालयों के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने, शारीरिक शिक्षकों के पदनाम परिवर्तन करने, 30 जून 2018 तक सी.ए.एस. लाभ हेतु पात्र शिक्षकों के आवेदन पत्र मंगवाने, मंत्रालयिक कर्मचारियों एवं प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति करने, जनवरी 2006 से जून 2006 के मध्य वेतन वृद्धि वाले शिक्षकों को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने, विश्वविद्यालयों में शिक्षकों एवं कर्मचारियों की कमी दूर करने सहित अन्य लम्बित समस्याओं के सकारात्मक समाधान की मांग संगठन द्वारा की गई। संगठन ने 30 जुलाई 2018 को उच्च शिक्षा मंत्री से 2013 के बाद लंबित पे बैंड 4 शीघ्र देने, महाविद्यालयों में प्राचार्यों की नियुक्ति, शिक्षकों के रिक्त पदों पर नवीन नियुक्तियां तथा आरवीआरईएस शिक्षकों की समस्याओं के समाधान आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा की। मंत्री जी ने बताया कि पे माइनस पेंशन के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों के नियुक्ति के आदेश जारी किए जा रहे हैं । नवीन चयनित शिक्षकों की नियुक्ति तथा प्राचार्य की डीपीसी के नियम शीघ्र जारी करवाने हेतु लोक सेवा आयोग अध्यक्ष श्री दीपक उप्रेती से उनकी वार्ता हुई है तथा शीघ्र ही इस संबंध में सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना है। वरिष्ठ व चयनित वेतनमान एवं पे बैंड 4 के लंबित मामलों के लिए उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करके इस मामले को एक सप्ताह में निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं । उन्होंने संगठन को विश्वास दिलाया कि अगले कुछ दिनों में ही शिक्षकों को सी.ए.एस. संबंधी अधिकार मिल सकेगा तथा शेष सभी समस्याओं पर भी उन्होंने सकारात्मक कदम उठाने का विश्वास दिलाया।

4. **सी.ए.एस. हेतु पात्र शिक्षकों को पूर्व प्रचलित नियमों से लाभ देने के आदेश जारी** – संगठन के निरन्तर प्रयत्नों एवं दबाव के चलते अन्तत: आयुक्तालय द्वारा गत 2 अगस्त 2018 को दिनांक 30 जून 2017 तक पे बैंड 4 के पात्र सहायक आचार्यों हेतु विभाग के पत्रांक एफ1(06) शिक्षा-4/2010 दिनांक 8 मई 2013 द्वारा जारी योजना के अनुसार ए.पी.आई. अंक की गणना किए जाने के आदेश प्रसारित कर दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि जून 2013 के बाद पे बैंड 4 हेतु पात्र शिक्षकों के एपीआई अंक निर्धारण में अनेक समस्याएं आईं थीं । संगठन के पास यह विषय पहुंचने के बाद संगठन ने निरंतर इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री जी एवं अन्य अधिकारियों के समक्ष शिक्षकों का पक्ष तथ्यों और तर्कों के साथ रखा था। कार्मिक, वित्त एवं उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की विभिन्न आपत्तियों का समुचित समाधान करने में संगठन ने प्रमुख भूमिका निभाई, साथ ही इस पूरे विषय में उच्च शिक्षा मंत्री जी का सकारात्मक सहयोग रहा। फलत: मई 2013 में राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र के अनुसार एपीआई अंक गणना करने

के आदेश आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी किए गए। संगठन अपेक्षा करता है कि 30 जून 2017 तक पात्र शिक्षकों को सी.ए.एस. का लाभ शीघ्र ही प्रदान किया जाएगा।

5. **यू.जी.सी.द्वारा नवीन रेगुलेशन जारी** – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी रेगुलेशन 2018 दिनांक 18 जुलाई 2018 को जारी कर दिया गया है । रुक्टा (राष्ट्रीय) ने यू.जी.सी. द्वारा जारी नवीन रेगुलेशन का स्वागत करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकरजी एवं यूजीसी अध्यक्ष का धन्यवाद ज्ञापित किया है कि उन्होंने संगठन द्वारा प्रस्तुत सुझावों और माँगो में से कई पर सकारात्मक रूख दर्शाते हुए व्यापक शिक्षा और शिक्षक हित में रेगुलेशन में प्रावधान किए हैं। नवीन रेगुलेशन में अत्यंत विवादित एपीआई पीबीएएस की विदाई की गई है तथा सीएएस योजना के अंतर्गत पदोन्नति प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। एम.फिल. और पीएच.डी. जैसी उच्चतर शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली वेतन वृद्धियों को संगठन के तर्क से सहमत होते हुए पुन: प्रारम्भ किया गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की ठहराव अवधि पूर्व में प्रस्तावित 7 घंटे के स्थान पर संगठन की माँग के अनुसार 5 घंटे ही रखी गई है। शिक्षकों का अध्यापन कार्य भार ,जो पूर्व में न्यूनतम 14 से 16 घंटे प्रस्तावित था, में से संगठन की आपत्ति के बाद न्यूनतम शब्द हटा दिया गया है। लंबित सीएएस पदोन्नति प्रकरणों में एपीआई की छूट अवधि नवीन रेगुलेशन की अधिसूचना जारी होने की तिथि तक बढ़ा दी गई है। संगठन के निरंतर दबाव के चलते अंतत: ओरिएंटेशन /रिफ्रेशर कोर्स में छूट की अवधि 31 दिसंबर 2018 तक की गई है। महाविद्यालयों में प्रोफेसर के पदों की सीमा, जो पूर्व के रेगुलेशन में थी, हटा दी गई है। स्नातक व स्नातकोत्तर प्राचार्यों को एक ही प्रोफेसर ग्रेड में रखा गया है। एक रेगुलेशन से दूसरे रेगुलेशन में स्मूथ मूवमेंट के लिए 3 वर्ष का विकल्प दिया गया है। सभी विश्वविद्यालयों से नवीन रेगुलेशन को 6 माह के भीतर लागू करने की बात कही गई है।

इन सब शिक्षक व शिक्षा हितकारी प्रावधानों के किए जाने के बाद भी कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण मुद्दे हैं जो संगठन के लिए चिंता के विषय हैं तथा उच्च शिक्षा व शिक्षकों के व्यापक हित में जिनके विषय में शीघ्र सकारात्मक निर्णय करना अपेक्षित है – देशभर में उच्च शिक्षा का एक समान स्तर बनाए रखने तथा शिक्षकों की एक समान सेवा शर्तों व वेतनमान के लिए आवश्यक है कि नवीन वेतनमान लागू करने में आए अतिरिक्त वित्तीय भार का न्यूनतम 80 प्रतिशत कम से कम 5 वर्ष तक केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को पुनर्भरण किया जाए। उच्च शिक्षा की विशिष्टता को देखते हुए तथा सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए इंडेक्स ऑफ रेशनलाइजेशन न्यूनतम 2.72 रखा जाए तथा वेतन नियतन करते समय न्यूनतम गुणांक 2.67 किया जाए। कॅरियर एडवांसमेंट योजना के अंतर्गत महाविद्यालयों में संसाधनों एवं अवसरों की उपलब्धता की न्यूनता को देखते हुए एसोसिएट प्रोफेसर लेवल तक पीएचडी की बाध्यता को समाप्त किया जाए। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत पीएचडी आदि डिग्री प्राप्त में लगे समय को नियुक्ति एवं पदोन्नति हेतु शैक्षणिक एवं शोध अनुभव के रूप में गिना जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालयों द्वारा यू.जी.सी. रेगुलेशन 2009 को लागू करने की तिथि तक पंजीकृत अभ्यर्थियों को नेट से छूट प्रदान की जाए। कुलपति पद हेतु विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में प्रोफेसर पद पर 5 वर्ष के अनुभव या 25 वर्ष के कुल अध्यापन अनुभव के प्रोफेसर को पात्र माना जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर पारदर्शिता से चयन हेतु अभ्यर्थी की अकादमिक उपलब्धियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत वेटेज दिया जाए। जर्नल के संपादन, कांफ्रेंस में भाग लेने, लोकप्रिय लेख आदि के लिए रिसर्च पॉइंट्स दिए जाएँ।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और रुक्टा(राष्ट्रीय) के ढाई वर्ष से अधिक के संघर्ष का परिणाम है कि अंतत: नवीन रेगुलेशन में शिक्षक हित की बहुत सी बातों को हम केंद्र सरकार से मनवा पाए। नवीन यू.जी.सी. वेतनमान के लिए कमेटी गठित करवाने के प्रयासों से लेकर चौहान समिति, गुप्ता समिति, यू.जी.सी. अध्यक्ष, यू.जी.सी. सचिव तथा मानव संसाधन विकास मंत्री आदि संबंधित पक्षों के समक्ष तथ्यों और तर्कों के आधार पर मजबूती से और बार- बार शिक्षकों का पक्ष रखा गया। निरंतर पत्राचार, ज्ञापन और भेंट वार्ताओं में शिक्षकों की भावनाओं को संबंधित पक्षों तक पहुंचाया गया, उनकी मांगों के औचित्य को समझाया गया; परिणाम सामने हैं। बहुत कुछ ठीक हुआ है, काफी ठीक होना बाकी है। किंतु जितना मिला है इस उपलब्धि से ही प्रसन्न और संतुष्ट हो जाना यह संगठन की कार्य पद्धति में नहीं है। जिन बातों को लेकर हम अब तक संघर्ष करते आए हैं उनको शिक्षक हित में मनवाने तक हमारे प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से आदेश जारी किए हैं ,उन आदेशों को अपने राज्य में मनवाना और शीघ्रताशीघ्र उनका लाभ दिलवाना,इस हेतु संगठन प्रयासरत है।

6. **लोक सेवा आयोग अध्यक्ष से भेंट** – संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 10 अगस्त 2018 को राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यक्ष श्री दीपक उप्रेती से मिलकर उन्हें नवीन दायित्व ग्रहण करने की शुभकामनाएँ एवं बधाइयां दी। श्री दीपक उप्रेती के साथ चली लंबी भेंटवार्ता में महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण हो रही परेशानियों को संगठन महामंत्री द्वारा रखा गया। उन्हें बताया गया कि पिछले 3 वर्ष से चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया लंबित होने के कारण न केवल योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है वरन् राज्य की उच्च शिक्षा एवं विद्यार्थी हित भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। श्री उप्रेती जी ने प्रत्येक तथ्य को ध्यान से सुना तथा संगठन को बताया कि उन्होंने इस विषय को प्राथमिकता से लिया है तथा इस संबंध में अधिकारियों-कार्मिकों को कार्य 15 अगस्त तक संपन्न करने के निर्देश दिये हैं। उनकी इस पहल के कारण कॉलेज शिक्षक भर्ती परीक्षा के रसायन शास्त्र एवं ए.बी.एस.टी. विषयों का परिणाम घोषित किया जा चुका है तथा शेष विषयों के परिणाम भी अगले कुछ दिनों में घोषित कर राज्य सरकार को नियुक्ति हेतु अभिशंषा भेज दी जाएगी। विश्वास है कि शिक्षक भर्ती एवम नियुक्ति हेतु संगठन के निरन्तर प्रयासों की परिणति अगले कुछ दिनों में हो सकेगी।

7. **उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों के सम्मान हेतु आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ** – संगठन के लगातार प्रयासों के चलते अंतत: आयुक्त कॉलेज शिक्षा द्वारा उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी विषयों के शिक्षकों, शारीरिक शिक्षा अधिकारियों व पुस्तकालयाध्यक्षों को सम्मानित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाने संबंधी आदेश 6 अगस्त को जारी कर दिए। रुक्टा (राष्ट्रीय) पिछले 2 वर्षों से उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों को राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किए जाने हेतु सतत संघर्ष कर रहा था, संगठन के संघर्षों के परिणाम स्वरूप बीकानेर अधिवेशन में उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी ने उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों के सम्मान की घोषणा की थी। राज्य की उच्च शिक्षा के लंबे इतिहास में यह अपेक्षित कार्य पहली बार होने जा रहा है। संगठन इसके लिए राज्य सरकार को धन्यवाद प्रेषित करता है तथा आप सब से आग्रह करता है कि अपने संस्थान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को आवेदन करने हेतु प्रेरित करें।

8. **पे माइनस पेंशन आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति हेतु आदेश जारी** – लोकसेवा आयोग से चयन उपरांत नवीन नियुक्ति के लिए संगठन निरंतर प्रयासरत है। कुछ कानूनी मसले हैं जिन्हें हल करने एवं नियुक्ति व शेष चयन प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न करने हेतु संगठन ने उच्च शिक्षा मंत्रीजी व लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से मिलकर दबाव बनाया है। संगठन को भरोसा दिलाया गया है कि सरकार व आयोग इसे प्राथमिकता से ले रहे हैं

तथा शीघ्र ही रुके हुए परिणामों की घोषणा व नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। इस बीच रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु संगठन ने पे माइनस पेंशन के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए भी दबाव बनाया था। वित्त विभाग की कतिपय आपत्तियों पर संगठन द्वारा समुचित पक्ष प्रस्तुत किया गया। फलस्वरूप आयुक्तालय द्वारा 1 अगस्त 2018 को पे माइनस पेंशन के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया हेतु आदेश जारी किए गए।

9. **30 जून 2018 तक सी.ए.एस. हेतु पात्र शिक्षकों से आवेदन पत्र आमंत्रण की माँग** - 30 जून 2013 के पश्चात् पात्र महाविद्यालय शिक्षकों को पे बैंड 4 का लाभ दिया जाना शेष है। इस संबंध में संगठन के प्रयासों से 30 जून 2017 तक वरिष्ठ/चयनित वेतमान एवं पे बैंड 4 के पात्र शिक्षकों के आवेदन मगाये जा चुके हैं तथा ए.पी.आई. गणना हेतु समुचित आदेश जारी किए गए हैं। संगठन ने उच्च शिक्षा मंत्रीजी एवं विभाग के अधिकारियों को पत्र लिख कर 30 जून 2018 तक सी.ए.एस. हेतु पात्र शिक्षकों के आवेदन पत्र मंगवाने की माँग की है। संगठन ने बताया कि राज्य सरकार के नियमानुसार सी.ए.एस. के लाभ के लिए ड्यू दिनांक तक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की आवश्यकता होती है इस कारण पूर्व में 30 जून 2017 तक ही सी.ए.एस. में वरिष्ठ/चयनित वेतमान तथा पे बैंड 4 के पात्र शिक्षकों से आवेदन मांगे गए थे। चूंकि गत अकादमिक सत्र 30 जून 2018 को समाप्त हो चुका है एवं अधिकांश महाविद्यालयों में सत्र 2017-18 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भी भरे जा चुके हैं। ऐसे में 30 जून 2017 तक पे बैंड 4 के पात्र शिक्षकों के लिए ए.पी.आई. अंकों की गणना प्रपत्र के साथ ही 30 जून 2018 तक वरिष्ठ/चयनित वेतनमान एवं पे बैंड 4 के पात्र शिक्षकों से भी सी.ए.एस. लाभ हेतु आवेदन भरवाए जाना न्यायसंगत होगा।

10. **प्रयोगशाला सहायकों के नियुक्ति आदेश जारी** - महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों के कमी के मुद्दे को संगठन निरंतर उठाता रहा है। प्रयोगशाला सहायकों की काउंसलिंग के बाद कतिपय अधिकारियों की टिप्पणियों के आधार पर प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्तियां रोक दी गई थीं। संगठन के संज्ञान में आते ही उच्च शिक्षा मंत्रीजी से मिलकर संपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए तथा इस विषय में नियुक्ति करवाने हेतु निरंतर संघर्ष किया। परिणामत: 2 अगस्त 2018 को 93 प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं।

11. **प्राचार्यों के वेतनवृद्धि आदेश जारी** - महाविद्यालयों के प्राचार्यों के वेतन वृद्धि आदेश आयुक्तालय द्वारा जारी किए जाते हैं। पिछले कई वर्षों से प्राचार्यों के वेतन वृद्धि आदेश जुलाई माह के स्थान पर 3 से 4 माह विलम्ब से प्रसारित हो रहे थे जिसके कारण उन्हें अपना वित्तीय अधिकार देरी से मिल रहा था। संगठन के प्रयासों से पिछले वर्ष उक्त आदेश जुलाई माह में प्रसारित हो गए थे। इस बार भी संगठन के प्रयासों से गत 10 जुलाई को महाविद्यालयों के प्राचार्यों के वार्षिक वेतन वृद्धि आदेश प्रसारित हो गए हैं।

12. **वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान के एरियर भुगतान का स्पष्टीकरण जारी** - संगठन के प्रयास से 25 जनवरी 2018 को पात्र शिक्षकों को सी.ए.एस. के तहत संशोधित रनिंग पे बैण्ड एवं ग्रेड पे का लाभ प्रदान करने के आदेश प्रसारित किए गए थे। कतिपय महाविद्यालयों ने सी.ए.एस. लाभ का एरियर भुगतान नहीं किया। प्रकरण की जानकारी मिलने पर संगठन ने विभाग के अधिकारियों से इस विषय पर चर्चा की। संगठन के प्रयत्नों से दिनांक 19-7-2018 को आयुक्तालय द्वारा एरियर भुगतान वेतन मद से करने के आदेश प्रसारित कर दिए गए।

13. **प्रतिदिन उपस्थिति ई-मेल द्वारा भेजने का विरोध** - आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा ने आदेश क्रमांक एफ 7(4)अकाद/आकाशि/प्रवेश नीति/2016/1105 दिनांक 1 अगस्त 18 के द्वारा सभी राजकीय महाविद्यालयों के

प्राचार्यों को एक प्रारूप भेजकर कक्षावार, वर्गवार, संकायवार एवं कालांशवार विद्यार्थियों की उपस्थिति सूचना एक्सेल शीट में प्रतिदिन आयुक्तालय को भेजने के आदेश प्रसारित किए हैं। संगठन ने उच्च शिक्षा मंत्रीजी को पत्र लिख कर इस आदेश को पूर्णत: अव्यावहारिक एवं अनावश्यक रूप से महाविद्यालयों के दैनन्दिन प्रशासनिक कार्यों को आयुक्तालय पर केन्द्रित करने का प्रयास बताते हुए वापस लेने की मांग की है। संगठन ने मंत्रीजी को पत्र में अवगत करवाया है कि इस तरह के आदेश से प्राचार्यों के महत्त्व को नकार कर अनावश्यक रूप से ऑफिस कार्य में वृद्धि की जा रही है। लम्बी प्रवेश प्रक्रिया, छात्रसंघ चुनाव सहित अनेक ऐसे कार्य हैं जिनसे महाविद्यालयों का शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे में प्रतिदिवस सभी शिक्षकों से विस्तृत उपस्थिति सूचना संधारण कर उसे मेल करने में मानवीय श्रम व्यर्थ जाएगा। समस्त निरीक्षण अथवा जानकारी का केन्द्रीकरण करना सरकार के अच्छे प्रशासन की भावना पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। संगठन ने मंत्रीजी के ध्यान में लाया है कि अधिकांश महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों की भारी कमी है। महाविद्यालयों में संसाधनों की अल्पता है जबकि गैर शैक्षणिक कार्य निरन्तर बढ़े हैं, अत: उचित यह होगा कि शैक्षणिक गुणवत्ता की ओर ध्यान देने के लिए उचित व्यवस्थाओं का निर्माण करते हुए शिक्षण कार्य हेतु अधिकाधिक अनुकूल माहौल निर्माण किया जाए।

14. **कार्य व्यवस्थार्थ लगाए गये शिक्षकों को विराम भत्ता देने की मांग** – आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा ने आदेश क्रमांक एफ1(01)स्था/आकाशि/18/पार्ट/4436 दिनांक 2 अगस्त 18 के द्वारा आयुक्तालय के विभिन्न आदेशों से शिक्षकों को सीमित अवधि पर अन्यत्र कार्य व्यवस्थार्थ लगाने पर उन्हें केवल एक बार का यात्रा भत्ता ही दिए जाने एवं कार्य व्यवस्थार्थ अवधि का विराम भत्ता नहीं देने के निर्देश जारी किए हैं। संगठन ने उक्त आदेश को नियम विरुद्ध बताते हुए उच्च शिक्षा मंत्रीजी एवं विभाग के अधिकारियों को पत्र लिख कर विरोध दर्ज करवाया है। संगठन ने मंत्रीजी को लिखे पत्र में बताया है कि जब किसी शिक्षक को मूल महाविद्यालय से अन्यत्र महाविद्यालय में सीमित अवधि के लिए लगाया जाता है तो शिक्षक का परिवार उसके मूल महाविद्यालय स्थान पर ही निवास करता है कार्यव्यवस्थार्थ लगाये गए शिक्षक को सीमित अवधि के लिए अस्थाई निवास एवं भोजन व्यवस्था करनी होती है। राज्य एवं केन्द्र सरकार की सभी सेवाओं में राजकार्य से मुख्यालय से अन्यत्र जाने पर यात्रा भत्ता के साथ नियमानुसार राजकार्य अवधि का डी.ए. दिया जाता है। संगठन ने मंत्रीजी के ध्यान में यह भी लाया कि राजस्थान सेवा नियमों में कार्यव्यवस्थार्थ लगाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर प्रतिनियुक्ति पर लगाया जाता है, जिसमें नियमानुसार प्रतिनियुक्ति भत्ता इत्यादि देय होते हैं। इस प्रकार कार्यव्यवस्थार्थ लगाए जाने के आदेश ही मूलत: नियम विरुद्ध हैं। संगठन ने मंत्रीजी से कार्यव्यवस्थार्थ/प्रतिनियुक्ति पर लगाए गए शिक्षकों को विराम भत्ता दिए जाने के आदेश प्रसारित करने की मांग की है।

15. **उच्च शिक्षा आयोग के संबंध में सुझाव प्रस्तुत** – अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने यू.जी.सी. अध्यक्ष प्रो. डी. पी. सिंह से मिलकर प्रस्तावित उच्च शिक्षा आयोग के संबंध में लिखित सुझाव प्रस्तुत किए। महासंघ ने यू.जी.सी. को समाप्त करने पर प्रश्नचिह्न लगाते हुए इस संबंध में विस्तृत चर्चा की आवश्यकता जताई। महासंघ ने उच्च शिक्षा को नौकरशाही के नियंत्रण से मुक्त करने, आयोग के सभी प्रमुख पदों पर शिक्षाविदों की ही नियुक्ति करने, संस्थानों के प्रत्यायन हेतु शिक्षाविदों की पूर्णत: स्वायत्त एजेंसी बनाने, उच्च शिक्षा संस्थानों को विभिन्न अनुदान देने हेतु अलग से स्वतंत्र संस्था बनाने, अलग-अलग नियामक परिषदों के कार्य को एकीकृत रूप से सम्पन्न करने जैसे सुझाव दिए हैं। महासंघ के प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष प्रो. जे. पी. सिंघल, संगठन मंत्री श्री महेन्द्र कपूर, सचिव डॉ. मनोज सिन्हा तथा संयुक्त सचिव डॉ. नारायण लाल गुप्ता शामिल थे।

16. **यू.जी.सी. अधिकृत सूची से हटाए गए जर्नल्स के संबंध में पक्ष प्रस्तुत** – यू.जी.सी. द्वारा 4 मई 2018 को बिना उचित प्रक्रिया अपनाए 4000 से अधिक जर्नल्स को यू.जी.सी. के स्वीकृत जर्नल्स की सूची से हटा दिया गया। इस संबंध में शिक्षकों का पक्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा मजबूती से एवं त्वरित रूप से रखा गया। शैक्षिक महासंघ के दबाव के चलते अंतत: यू.जी.सी. को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा कि इन जर्नल्स में पूर्व में छपे/स्वीकृत शोध पत्रों के अंक देय होंगे तथा हटाए गए जर्नल्स कतिपय मापदंड पूर्ण करने के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा पुन: प्रस्तावित किए जा सकेंगे।

17. **30 जून 2017 तक पे बैंड 4 हेतु पात्र शिक्षकों के आवेदन पत्र अग्रेषण के संबंध में स्पष्टीकरण जारी** – संगठन के प्रयासों से 30 जून 2017 तक पे बैंड 4 हेतु पात्र शिक्षकों के ए.पी.आई. अंकों की गणना राज्य सरकार के दिनांक 8 मई 2013 के आदेशानुसार किए जाने के आदेश प्रसारित हुए। आयुक्तालय द्वारा पूर्व में अप्रेल 2018 माह में जो ए.पी.आई. गणना कर आवेदन पत्र आयुक्तालय को प्रेषित करने के निर्देश जारी किए थे उनमें अनेक विसंगतियाँ थीं। जिनके निराकरण के लिए संगठन लगातार प्रयत्नशील रहा। इसी कारण उक्त प्रक्रिया को 7 मई 2018 को स्थगित कर दिया गया था। किन्तु कतिपय महाविद्यालयों द्वारा पे बैंड 4 हेतु आवेदन पत्र आयुक्तालय को प्रेषित कर दिए थे। ऐसे में दिनांक 2 अगस्त 2018 के आदेश के पश्चात् ऐसे महाविद्यालयों में पे बैंड 4 हेतु पुन: आवेदन को लेकर असमंजस की स्थिति हो गई थी। प्रकरण संगठन के ध्यान में आने पर संगठन ने आयुक्तालय अधिकारियों से विस्तृत चर्चा कर समुचित दिशा-निर्देश जारी करने की माँग की थी। आयुक्तालय द्वारा संगठन की भावनानुसार कार्यवाही करते हुए पत्र क्रमांक एफ.1(92)पी.एस./निकाशि/13/पार्ट/1159 दिनांक 6 अगस्त 2018 द्वारा समुचित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

18. **बांसवाड़ा में कृषि संकाय स्थानीय महाविद्यालय के स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय के अधीन प्रारम्भ करने की मांग** – मुख्यमंत्रीजी की घोषणा के अनुरूप गत 6 जुलाई को शिक्षा विभाग ग्रुप (3) राजस्थान सरकार ने राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा में कृषि संकाय प्रारम्भ करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की है। संगठन ने उच्च शिक्षा मंत्रीजी को पत्र लिख कर इसका संचालन सामान्य शिक्षा महाविद्यालय में किए जाने की कठिनाईयों के बारे में अवगत करवाया है। संगठन ने मंत्रीजी के ध्यान में लाया है कि कृषि एक तकनीकी विषय है इसके संचालन के लिए कृषि भूमि, फार्म, पशुपालन, डेयरी आदि अत्यन्त आवश्यक है, जो कि सामान्य शिक्षा महाविद्यालयों में उपलब्ध नहीं होते हैं। गत कुछ वर्षों में कृषि शिक्षा उन्नयन हेतु सरकार ने भरतपुर, लालसोट, कोटा, जोधपुर, सुमेरपुर आदि में कृषि विश्वविद्यालय के अधीन ही पृथक् कॉलेज खोले हैं, जिनमें अपेक्षाकृत कृषि शिक्षा का प्रसार गुणवत्ता की दृष्टि से कहीं बेहतर है। संगठन ने मंत्रीजी के ध्यान में यह भी लाया कि कृषि संकाय संचालन को आई.सी.ए.आर. से स्थाई मान्यता इसे पृथक् महाविद्यालय में संचालित करने पर मिलती है इसी कारण सवाईमाधोपुर, चिमनपुरा एवं उनियारा में संचालित कृषि संकाय को अभी तक आई.सी.ए.आर. से स्थाई मान्यता नहीं मिल पाई है। संगठन ने मांग की है कि नए कृषि संकाय को राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा में संचालित करने के स्थान पर बांसवाड़ा में ही महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर से सम्बद्ध कृषि अनुसंधान केन्द्र अथवा कृषि विकास केन्द्र में संचालित किया जाना चाहिए। इन केन्द्रों पर पर्याप्त भवन, कृषि फार्म, पशुपालन हेतु डेयरी एवं शैक्षणिक स्टॉफ आदि उपलब्ध है जिससे यहाँ कृषि संकाय प्रारम्भ करने से राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा तथा कृषि शिक्षा का गुणात्मक प्रसार भी होगा।

सांगठनिक एवं वैचारिक गतिविधियाँ

1. **प्रदेश चिंतन वर्ग सम्पन्न** - संगठन का प्रदेश चिंतन वर्ग दिनांक 15 से 17 जून 2018 तक जयपुर के ग्लोबल इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी परिसर में सम्पन्न हुआ। सात विविध सत्रों में आयोजित इस वर्ग के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सम्पर्क प्रमुख प्रो. अनिरुद्धजी देशपाण्डे, सह क्षेत्र प्रचारक श्री निम्बारामजी, क्षेत्र बौद्धिक प्रमुख श्री ग्यारसीलालजी, क्षेत्र कार्यवाह श्री हनुमानसिंहजी, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. जगदीशप्रसादजी सिंघल व राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री महेंद्रजी कपूर ने उपस्थित रहकर सम्भागियों को पाथेय प्रदान किया।

वर्ग के उद्घाटन सत्र में श्री निम्बारामजी ने कहा कि हिंदुत्व भारत का स्वभाव, दर्शन और उसकी आत्मा है। हिंदू दर्शन को निकाल देने पर भारत केवल एक भूखंड मात्र रह जाएगा। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की हमारी समृद्ध अवधारणा वर्तमान वैश्वीकरण से पूर्णतया भिन्न है। वैश्वीकरण उपभोक्तावाद को बढ़ावा देता है, जबकि हम प्रकृति से समन्वय की बात करते हैं। उन्होंने नेशन व राष्ट्र में अंतर स्पष्ट करते हुए बताया कि नेशन केवल एक राजनैतिक-भौगोलिक इकाई का अर्थ देता है जबकि राष्ट्र भावात्मक एवं सांस्कृतिक संकल्पना है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी हिंदुत्व को जीवन-पद्धति तथा जीवन- दर्शन स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि पूजा-पद्धति राष्ट्रीयता नहीं है बल्कि समान शत्रु-मित्र भाव को मानने वाला ही सच्चा राष्ट्रभक्त होता है। उन्होंने आह्वान किया कि आज राष्ट्रप्रेम से युवा पीढ़ी को डिगाने की कोशिश हो रही है, ऐसी स्थिति में हमें प्रमुख भूमिका में आकर अपनी संस्कृति के प्रति गौरव की अनुभूति स्थापित करनी होगी। वर्ग के अन्य सामूहिक सत्र में प्रो. अनिरुद्धजी देशपाण्डे ने संगठन के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को रेखांकित करते हुए वर्ग में भाग ले रहे शिक्षक बंधु-भगिनियों का आह्वान किया कि मानविकी व समाज-विज्ञानों के विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रमों पर अब भी औपनिवेशिक काल की छाया मंडरा रही है, जबकि हमें स्वतंत्र हुए सात दशक बीत चुके हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम इस छाया से शीघ्रातिशीघ्र मुक्त हों। प्रो. देशपाण्डे ने कहा कि एक शिक्षक का कर्तव्य-बोध कक्षाओं तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। एक शिक्षक का दायित्व है कि वह समाज के प्रत्येक अंग को अपने सद्गुणों से आलोकित करे। उन्होंने कहा कि परिवार के बाद समाज में व्यक्ति निर्माण का सबसे विश्वसनीय घटक शिक्षक ही होता है। उन्होंने शिक्षक के लिए स्टेकहोल्डर शब्द को अनुचित बताते हुए कहा कि स्टेकहोल्डर में कुछ प्राप्त करने का भाव आता है जो पश्चिम में प्रचलित उपयोगितावाद में प्रयोग किया जा सकता है; किंतु भारत में शिक्षक समाज परिवर्तन का वाहक है। उन्होंने अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के संबंध में विचार रखते हुए बताया कि अंग्रेजी का एक भाषा के रूप में अध्ययन करना ठीक है; किंतु इसके कारण विद्यार्थी में अपनी मातृभाषा के लिए तुच्छता का भाव पैदा हो, यह चिंतनीय है। उन्होंने चिंता प्रकट करते हुए कहा की संवाद रहित टेक्नोलॉजी द्वारा ज्ञान नहीं दिया जा सकता। ज्ञान के लिए सिर्फ गूगल पर निर्भर रहना उचित नहीं है। टेक्नोलॉजी साध्य के स्थान पर साधन के रूप में प्रयुक्त हो तथा शिक्षा विद्यार्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने वाली हो तभी शिक्षा के व्यापक लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है। एक और सामूहिक सत्र में श्री हनुमानसिंहजी ने बताया कि एक राष्ट्र -सापेक्ष शिक्षक-संगठन के कार्यकर्ता का कर्म-अधिष्ठान राष्ट्र ही होना चाहिए। उन्होंने श्रीमद्भगवद्गीता को उद्धृत करते हुए कहा कि जो करणीय है, वही कर्म है। उन्होंने कहा कि एक कार्यकर्ता को स्थितप्रज्ञ रहते हुए समभाव से अपने करणीय कार्यों में सदैव रत रहना चाहिए। भ्रमर-कीट न्याय के सिद्धांत के आधार पर हमें दूसरों को प्रेरित करना चाहिए कि वह हमारे अधिष्ठान को समझें। श्री हनुमानसिंहजी का विचार था कि समाज को विभेदित करने के प्रत्येक प्रयत्न को विफल करके हमें एक समरस समाज की रचना में

अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारा कल्याण है। उन्होंने श्री गुरुजी द्वारा उडुपी सम्मेलन में धर्माचार्यों को एक मंच पर लाने का उदाहरण देते हुए बताया कि अहंकार को विलगित कर देने से आप परस्पर विरोधी चरित्रों को भी एक मंच पर बैठा सकते हैं। उन्होंने आह्वान किया कि हमें मन कर्म वचन से इतना पवित्र होना चाहिए कि कोई अपारदर्शिता नहीं रहे। वर्ग के सामूहिक संवाद सत्र में हनुमान सिंह जी ने वर्तमान के वैचारिक संघर्ष की पृष्ठभूमि को रखते हुए कहा कि राष्ट्रीय विचार को लेकर एक बौद्धिक संघर्ष खड़ा किया गया है; किंतु यह निश्चित है कि विजय सत्य की ही होती है। संवाद सत्र में संभागियों द्वारा वर्तमान की चुनौतियां के संबंध में अपने अभिमत प्रकट किए। श्री हनुमान सिंह जी ने संभागियों द्वारा आए विभिन्न विषयों और प्रश्नों पर बोलते हुए कहा की विमर्श के लिए सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों रूपों में कार्य करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि कई स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका बहुत ही संदिग्ध रही है, वामपंथियों ने एनजीओ के माध्यम से ऐसा बड़ा विमर्श खड़ा किया है जो पूरी तरह अन्तरराष्ट्रीय षड्यंत्र के रूप में है। कम्युनिज्म का आधार वर्ग संघर्ष में है, इसके परिणामस्वरूप ये लोग देश में विभिन्न प्रकार के विभाजन के आंदोलन छेड़ते रहते हैं। उन्होंने इस संबंध में अध्ययन,लेखन व शोध में सक्रिय रुप से कार्य करने का आह्वान किया।

वर्ग में विभिन्न संभागों जयपुर, जोधपुर और चित्तौड़ के अनुसार चक्रीय बैठकों के रूप में तीन तकनीकी सत्र सम्पादित हुए, जिनमें सम्भागियों को श्री जगदीशप्रसादजी सिंघल, श्री महेंद्रजी कपूर व श्री ग्यारसीलालजी का पाथेय प्राप्त हुआ। श्री जगदीशप्रसादजी सिंघल ने संगठन की यात्रा और विचार-प्रवाह को स्पष्ट करते हुए कार्यकताओं का आह्वान किया कि वे संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय चिंतन-धारा का प्रसार करके अपने जीवन को सार्थक स्वरूप प्रदान करें। श्री सिंघलजी का विचार था कि शिक्षक में ही वह शक्ति निहित है, जिसके चलते हमारा राष्ट्र बड़े-बड़े संकट-वलयों से बाहर निकल सकता है। श्री महेंद्र कपूरजी ने अपने उद्‌बोधन में संगठन की गति-प्रगति को सतत बनाए रखने के विभिन्न साधनों का उल्लेख करते हुए कहा कि इकाई-स्तर पर सक्रियता बने रहना ही संगठन की सफलता का मूल आधार है। उन्होंने कहा कि हमारे विचार परिवार में नए सदस्यों को सम्मिलित करने का उद्यम लोगों को राष्ट्र-सेवा के पथ पर लाने का पुनीत अवसर होता है। हमें धीर-गम्भीर होकर इस दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। उन्होंने सम्भागियों से आह्‌वान किया कि वे प्रवास करने का अभ्यास अवश्य करें,क्योंकि प्रवास ही एक ऐसा माध्यम है - जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ते हुए हमें राष्ट्र-सेवा के लिए प्रवृत्त करता है। श्री ग्यारसीलाल जाट ने सम्भागियों को पद्धति के लक्ष्यों की जानकारी देते हुए संगठन की कार्यपद्धति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि हमारा संगठन एक व्यवस्थित नीति और परम्परा के अनुसार चलता है, जिसमें सभी कार्यकर्ता समान रूप से महत्त्व प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें कई जन्मों के पुण्य-प्रसाद स्वरूप मानव जीवन मिला है और इसकी सार्थकता इसी में है कि हम इसे राष्ट्र की सेवा में लगा दें। चक्रीय सत्रों में द्विआयामी संवाद की प्रक्रिया अपनाई गई। अधिकारियों ने स्वयं सम्भागियों से प्रश्न पूछे और उनके विचार जाने। सम्भागियों ने भी खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी तथा अपनी जिज्ञासाएँ भी प्रकट कीं, जिनका युक्तियुक्त रूप से समाधान किया गया। समारोप सत्र में प्रो. अनिरुद्धजी देशपाण्डे ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि राष्ट्रीय शब्द के प्रयोग करने से सिद्धांतों का एक समुच्चय हमारे ध्यान में आता है। इस देश की शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजों के प्रभाव के कारण हमारे मूल दृष्टिकोण से हमें दूर किया गया जैसे आर्यों को आक्रमणकारी व बाहर से आने वाला गलत सिद्धांत हमें पढ़ाया जाता रहा। उन्होंने कहा कि सामूहिकता हमारी आत्मीय पहचान है, संगठन की सक्रियता ही विचार के प्रवाह का आधार है। संगठन हमारे स्वार्थों की पूर्ति का साधन नहीं बल्कि भारत माता की जय के वृहद लक्ष्य का आधार है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विचार और संगठन की दो धाराओं का सहज सम्मिलन हमें सदा समाज एवं राष्ट्र की सेवा के लिए

प्रेरित और प्रोत्साहित करता रहेगा। इस वर्ग में प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों-महाविद्यालयों में कार्यरत दो सौ पंद्रह शिक्षक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

2. **विस्तृत कार्यकारिणी बैठक सम्पन्न** - संगठन की विस्तृत कार्यकारिणी बैठक 15 जून 2018 को डॉ. दिग्विजयसिंह की अध्यक्षता में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर में सम्पन्न हुई। सरस्वती वंदना से प्रारम्भ बैठक में सर्वप्रथम महामंत्री ने गत बैठक की कार्यवाही विवरण प्रस्तुत किया; जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। महामंत्री ने गत बैठक के पश्चात् संगठन की उपलब्धियों एवं गतिविधियों की विस्तृत जानकारी देते हुए सातवें वेतन, पे बैंड-4, नवीन नियुक्तियों, आर.वी.आर.ई.एस. शिक्षकों की समस्याओं, प्राचार्य पद हेतु चयन, प्रोफेसर पद हेतु चयन, अशैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती सहित अन्य समस्याओं पर संगठन के प्रयासों के बारे में सदन को अवगत कराया तथा निकट भविष्य में समस्याओं के समाधान हेतु आशा जताई। अगले सत्र में कार्यकारिणी सदस्यों ने शिक्षकों की अन्य समस्याओं को प्रस्तुत करते हुए संगठन से आवश्यक कार्यवाही हेतु अपेक्षा की। महामंत्री ने सदस्यों द्वारा उठाए गए विषयों के संबंध में संगठन द्वारा शिक्षकों की भावनानुसार प्रयास करने का विश्वास दिलाया। इसके बाद राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री महेन्द्र कपूर ने प्रबोधन करते हुए संगठन कार्य के दृढीकरण एवं विस्तार हेतु कार्यकर्ताओं को समर्पण भाव से कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने संगठन के कार्यक्रमों के उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए पूर्व नियोजित ढंग से कार्यक्रमों के आयोजन एवं समीक्षा की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि बैठक, प्रवास, कार्ययोजना एवं कार्य विभाजन जैसे सांगठनिक विषयों पर प्रतिबद्ध होकर कार्य करना संगठन के विस्तार एवं दृढता का मूल मंत्र है। बैठक के अन्तिम सत्र में वर्ष पर्यन्त होने वाली कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया गया। इसमें 2 से 16 जुलाई सदस्यता अभियान, 27 जुलाई गुरुवंदन कार्यक्रम, जुलाई-अगस्त माह में एक शिक्षक-एक वृक्ष कार्यक्रम, सितम्बर में विश्वविद्यालय सम्मेलन एवं विभागश: कार्यक्रम, अक्टूबर में राष्ट्रीय अधिवेशन, दिसम्बर-जनवरी में प्रदेश अधिवेशन, जनवरी माह में कर्तव्य बोध कार्यक्रम, मार्च माह में नवसंवत्सर कार्यक्रम तथा जून माह में अभ्यास वर्ग की योजना की गई। अध्यक्षीय उद्‌बोधन देते हुए संगठन अध्यक्ष डॉ. दिग्विजयसिंह ने इकाइयों की नियमित सार संभाल की आवश्यकता जताते हुए कार्यकारिणी सदस्यों को नियमित प्रवास हेतु कहा। अंत में गत बैठक के पश्चात् दिवंगत शिक्षक साथियों प्रो. हस्तीमल शर्मा-पाली, डॉ. शंकरलाल जाट-चिमनपुरा, प्रो. पी. डी. सिंघल-बालोतरा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट मौन रख कर श्रद्धांजलि दी गई। सामूहिक कल्याण मंत्र के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

3. **राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक अहमदाबाद में सम्पन्न** - अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 26 व 27 मई 2018 को अहमदाबाद (गुजरात) में सम्पन्न हुई जिसमें 18 राज्यों के 86 प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उद्‌घाटन के पश्चात् गत कार्यकारिणी बैठक के कार्य विवरण को महामंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। महासंघ से सम्बद्ध विभिन्न राज्य संगठनों एवं विश्वविद्यालय संगठनों द्वारा अपना विशेष कार्यवृत्त प्रस्तुत किया गया जिसमें 7वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन की स्थिति, नव वर्ष शुभेच्छा कार्यक्रमों, शिक्षक समस्याओं के समाधान के संबंध में किए गए आन्दोलन, कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग, संगोष्ठियाँ, महिला सम्मेलन, वार्षिक अधिवेशन, सामाजिक समरसता कार्यक्रम आदि की जानकारी प्रदान की गई। कार्यकारिणी के समक्ष 6 संगठनों - 1. देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी शैक्षिक संघ, इन्दौर (म. प्र.), 2. बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी शैक्षिक संघ, भोपाल (म. प्र.), 3. चौधरी रणवीरसिंह विश्वविद्यालय शैक्षिक संघ, जींद (हरियाणा), 4. भक्त फूलसिंह महिला विश्वविद्यालय शैक्षिक संघ, सोनीपत (हरियाणा), 5. कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी शैक्षिक संघ, कुरुक्षेत्र (हरियाणा), 6. जम्मू सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी शैक्षिक संघ, जम्मू कश्मीर की सम्बद्धता के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

किए गए जिन्हें स्वीकार करते हुए इन संगठनों को महासंघ ने सम्बद्धता प्रदान की एवं उनका महासंघ में स्वागत किया गया। 24-25 फरवरी 2018 को दिल्ली में सम्पन्न अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की समीक्षा की गई। कार्यक्रम की विषय वस्तु, सहभागिता, प्रमुख वक्ताओं, व्यवस्थाओं आदि की श्रेष्ठता स्वीकार करते हुए इस विषय पर और अधिक कार्य करने का निर्णय लिया गया। नव वर्ष के कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए उन्हें और अधिक विस्तार देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की संवर्गश: बैठक आयोजित की गई जिसमें शिक्षा एवं शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण के सुझाव दिए गए साथ ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को शिक्षकों के हित में सम्पूर्ण देश में एक समान लागू कराने पर भी विमर्श हुआ और आवश्यक कदम उठाने के सुझाव आए। 5, 6 एवं 7 अक्टूबर 2018 को इन्दौर (मध्य प्रदेश) में आयोजित होने वाले सातवें राष्ट्रीय अधिवेशन की सम्पूर्ण कार्ययोजना को महासंघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेन्द्रजी कपूर द्वारा सदस्यों के समक्ष रखा गया तथा उनसे सुझाव माँगे गए। अधिवेशन में शिक्षक समस्याओं पर चर्चा करने, प्रस्ताव पारित करने, खुला सत्र, संवर्गश: बैठक करने, तीन वैचारिक विमर्श आयोजित करने के साथ-साथ इसी अधिवेशन के दूसरे दिन चतुर्थ अ. भा. शिक्षक सम्मान कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। सम्बद्ध संगठनों के कार्यों की प्रदर्शनी, महासंघ के कार्यक्रमों की डाक्यूमेंट्री के साथ-साथ संबद्ध संगठनों की जानकारी से युक्त एक पुस्तिका का प्रकाशन करने पर भी सहमति बनी। महासंघ के आगामी कार्यक्रमों की श्रृंखला में उच्च शिक्षा संवर्ग की 10 जून 2018 को दिल्ली में आयोज्य बैठक की जानकारी भी दी गई। महासंघ के तीस वर्ष से अधिक की जीवन-यात्रा हम कहाँ से प्रारम्भ कर, कहाँ हैं? एवं कहाँ पहुँचना चाहते हैं? इस पर राष्ट्रीय संगठन मंत्री द्वारा चर्चा प्रारम्भ की गई। उपस्थित अधिकांश संगठनों ने अपने-अपने अनुभव बाँटते हुए अपने संगठन की भावी संकल्पना एवं कार्य विस्तार की रचना को स्पष्ट करते हुए यह स्वीकार किया कि अब महासंघ का अखिल भारतीय स्वरूप शासन, सरकार एवं शिक्षकों द्वारा स्वीकार किया जाने लगा है और शिक्षा के क्षेत्र में अब हमारी भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, अत: हमें पूर्ण निष्ठा एवं लगन से कार्य करते हुए प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं की सहायता से देश के सभी राज्यों में महासंघ की सशक्त उपस्थिति को साकार बनाना है। शाश्वत जीवन मूल्य जनजागरण अभियान पर उच्च शिक्षा प्रभारी महेन्द्र कुमार द्वारा चर्चा प्रारम्भ की गई। सदस्यों द्वारा अनेक सुझाव दिए गए और इस अभियान को सभी संगठनों द्वारा यशस्वी बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहने की आवश्यकता को स्वीकारते हुए पूर्ण प्रतिबद्धता से कार्य करने का संकल्प लिया। समारोप कार्यक्रम में महासंघ के अध्यक्ष प्रो. जे. पी. सिंघल ने अपने उद्बोधन में कहा कि महासंघ राष्ट्र की सेवा करने के कार्य में संलग्न प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं का ऐसा संगठन है जो शिक्षा के क्षेत्र में सत्य का प्रतिपादन करने की क्षमता रखता है। इसके लिए हमें शिक्षकों में ऐसा सामर्थ्य निर्माण करना होगा जिसमें वह अच्छे नागरिक बनाने, मानवीयता फैलाने एवं विनम्रता विकसित करने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि इस सबके लिए शिक्षकों को हृदय की शुद्धता, मस्तिष्क की स्पष्टता एवं कर्म की निष्ठा के साथ कार्य करना होगा। समापन सत्र में महासंघ की वेबसाईट www.abrsm.in का नए रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा शुभारम्भ किया गया। महासंघ के महामंत्री शिवानंद सिन्दनकेरा ने आभार व्यक्त किया। रुक्टा (राष्ट्रीय) से अध्यक्ष डॉ. दिग्विजयसिंह, सहसंगठन मंत्री डॉ. सुशील कुमार बिस्सु, डॉ. दीपक शर्मा एवं महामंत्री ने भाग लिया।

4. **उच्च शिक्षा संवर्ग की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक सम्पन्न** - अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के उच्च शिक्षा संवर्ग की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक 10 जून 2018 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। सम्पूर्ण देश के 20 राज्यों से आए विभिन्न राज्य संगठनों एवं विश्वविद्यालय संगठनों के 120 से अधिक अध्यक्षों एवं महामंत्रियों ने बैठक में भाग लिया।

संभागियों द्वारा यूजीसी के नवीन वेतनमानों एवं सेवा शर्तों पर गंभीर विचार-विमर्श कर आगामी रणनीति हेतु सुझाव दिए गए। कार्यसमिति द्वारा इस बात पर प्रसन्नता एवं संतोष व्यक्त किया गया कि महासंघ द्वारा समय-समय पर यूजीसी अध्यक्ष एवं मानव संसाधन विकास मंत्री से नियमित रूप से वार्ता कर शिक्षकों का पक्ष समुचित रुप से प्रस्तुत किया गया, फलस्वरूप पिछले रेगुलेशन की कई समस्याओं का समाधान हुआ। संभागियों द्वारा महासंघ को एपीआई पीबीएएस तंत्र को समाप्त करवाने, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों के पदों में एकरूपता लाने, स्नातक व स्नातकोत्तर प्राचार्य को एक ही प्रोफेसर ग्रेड में रखने की व्यवस्था करवाने, जुलाई 2016 तक एपीआई अंकों की बाध्यता को शिथिल करवाने,एसोसिएट प्रोफेसर हेतु पीएचडी सुपरविजन की आवश्यकता को समाप्त करवाने, वार्षिक इंक्रीमेंट हेतु जनवरी व जुलाई दो विकल्प की व्यवस्था होने, एक रेगुलेशन से दूसरे रेगुलेशन में स्मूथ मूवमेंट के लिए 2 वर्ष का प्रावधान करने , यू.जी.सी. जर्नल्स की लिस्ट में से बिना कारण हटाए गए जर्नल्स हेतु स्पष्टीकरण जारी करवाने जैसी उपलब्धियों के लिए महासंघ की जागरूकता एवं प्रयासों के लिए धन्यवाद व्यक्त किया गया।

कार्यसमिति सदस्यों ने नवीन सेवा शर्तें शीघ्र जारी करवाने, नवीन यू.जी.सी. वेतनमानों को पूरे देश में एक समान लागू करवाने, पीएचडी और एमफिल की वेतन वृद्धियों को पुन: चालू करवाने, सातवें वेतन आयोग को लागू करने हेतु राज्यों को केंद्रीय सहायता का अंश न्यूनतम 80 प्रतिशत 5 वर्ष तक देने, वेतन नियतन हेतु गुणांक न्यूनतम 2.67 करने, शिक्षकों की ठहराव अवधि 7 घंटे के स्थान पर 5 घंटे करने तथा वर्क लोड में न्यूनतम शब्द हटाने, असिस्टेंट प्रोफेसर (सलेक्शन स्केल) व एसोसिएट प्रोफेसर पद पर सीएएस प्रमोशन हेतु पीएचडी की अनिवार्यता वापस लेने, यूजीसी के माइनर व मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट जारी रखने, अतिथि अध्यापन व्यवस्था समाप्त कर सभी तरह के शैक्षणिक व अशैक्षणिक पदों को पूर्णतया भरे जाने, कोर्स वर्क हेतु सवैतनिक अवकाश की व्यवस्था करने अथवा सेवारत शिक्षकों को कोर्स वर्क से मुक्त करने, उच्च शिक्षा पर जीडीपी का न्यूनतम 6 प्रतिशत व्यय करने, असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयन प्रक्रिया को न्याय संगत बनाने सहित शिक्षक हित की अन्य समस्याओं के समाधान की मांग की। महासंघ के अध्यक्ष श्री जे. पी. सिंघल व उच्च शिक्षा संवर्ग के सचिव डॉ मनोज सिन्हा ने महासंघ के प्रयासों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि शीघ्र ही नवीन सेवा शर्तें जारी होनी है तथा अधिकांश समस्याओं को मजबूत ढंग से महासंघ द्वारा केंद्र सरकार के समक्ष रख दिया गया है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि सदस्यों की अपेक्षा के अनुरूप महासंघ इन समस्याओं को सुलझाने के लिए और गहन प्रयास करेगा। महासंघ के संगठन मंत्री श्री महेंद्र कपूर ने बैठक के अंतिम सत्र में कार्य के विस्तार और दृढीकरण की आवश्यकता जताते हुए गुरुवंदन, कर्तव्य बोध, नवसंवत्सर, शाश्वत जीवन मूल्य जैसे कार्यक्रमों हेतु और गंभीर प्रयासों की आवश्यकता जताई। उन्होंने आह्वान किया की अध्ययन, संपर्क, प्रेम और समर्पण यही संगठन को सम्यक् रूप से चालित करने का मूल मंत्र हैं। संगठन के महामंत्री श्री शिवानंद सिन्दनकेरा ने अक्टूबर माह में इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बैठक की अध्यक्षता प्रोफेसर प्रग्नेश शाह ने की तथा आभार डॉ नारायण लाल गुप्ता ने व्यक्त किया। रुक्टा (राष्ट्रीय) की ओर से अध्यक्ष व महामंत्री ने बैठक में भाग लिया।

5. **उच्च शिक्षा में नैतिकता एवं कार्य संस्कृति विषयक संगोष्ठी में सहभाग** - शैक्षिक मंथन संस्थान, जयपुर द्वारा जयपुर के शास्त्रीनगर स्थित विज्ञान पार्क में 8 जुलाई 2018 को 'उच्च शिक्षा में नैतिकता एवं कार्य संस्कृति' विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारम्भ डॉ. अरुण चतुर्वेदी, केबीनेट मंत्री, राजस्थान सरकार के मुख्य आतिथ्य में माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि अंग्रेजों ने इस देश की रीढ़ मानी जाने वाली समृद्ध शिक्षा पद्धति को जानबूझकर कमजोर व नष्ट-भ्रष्ट कर दिया

जिसके कारण इसकी वर्तमान स्थिति डिग्री प्रदान करने तक सीमित हो गई। उन्होंने कहा कि आज की हमारी शिक्षा-पद्धति को पुनः राष्ट्रभक्ति व संस्कारोन्मुखी बनाने की महत्ती आवश्यकता है। इस अवसर पर प्रमुख वक्ता के नाते यू.जी.सी. के चेयरमैन प्रो. धीरेन्द्र पाल सिंह ने कहा कि शिक्षक का सभ्य आचरण तथा सुसभ्य व्यक्तित्व विद्यार्थियों के मनमानस में आदर्शों की स्थापना में योग देता है। उन्होंने पं. मदन मोहन मालवीय जी का उल्लेख करते हुए बताया कि महाविद्यालय/विश्वविद्यालय, विद्यार्थियों की नर्सरी होती है। इस अवसर पर शैक्षिक मंथन मासिक पत्रिका का विमोचन किया गया। प्रो. जे. पी. सिंघल ने संगोष्ठी का विषय प्रवेश करते हुए कहा कि वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में शिक्षक अपनी कार्य-संस्कृति से प्रबुद्धजन एवं विद्यार्थियों को सही दशा व दिशा बताने का सामर्थ्य रखता है। इस अवसर पर शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री महेन्द्र कपूर ने संस्थान का परिचय व उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि समाज शिक्षकों से ही नैतिकता की अपेक्षा करता है, हमें समाज के इस विश्वास को बचाए व बनाए रखना है। संगोष्ठी-परिचय डॉ. दीपक कुमार शर्मा ने, स्वागत भाषण डॉ. कमल मिश्रा ने व सत्र संचालन डॉ. शिवशरण कौशिक ने किया। संगोष्ठी में दो तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया। प्रथम सत्र 'नैतिक मूल्यों की स्थापना में शिक्षक की भूमिका' विषय पर केन्द्रित रहा जिसमें मुख्य वक्ता प्रो. पी. सी. त्रिवेदी, पूर्व कुलपति ने कहा कि आज की शिक्षा का उद्देश्य 'सा विद्या या विमुक्तये' के स्थान पर 'सा विद्या या नियुक्तये' हो गया अर्थात् नियुक्ति (वृत्ति) आधारित शिक्षक अर्थ की मानसिकता से प्रेरित हो मात्र पाठ्यक्रम पूरा कराता है। सत्र के अध्यक्ष प्रो. नंद किशोर पाण्डेय, निदेशक केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा ने बताया कि मौजूदा पाठ्यक्रमों में हमारी पुरातन पद्धतियों का तथा प्राचीन ज्ञान का कुछ संस्थानों में समावेश किया जाकर राष्ट्रीय जागरण में योग दें। द्वितीय तकनीकी सत्र को संबोधित करते हुए प्रो. जे. पी. सिंघल ने कहा कि शिक्षक समाज का दर्पण होता है, उसकी भूमिका संस्कृति निर्माण के साथ आचरण से शिक्षा देने जैसे होगी तो अच्छी संस्कृति के मानदण्ड व जीवन मूल्यों की स्थापना में योगकारी होगा। इस अवसर पर डॉ. नारायण लाल गुप्ता ने कहा कि कुशलता पूर्वक कर्म करना ही योग है। यह वैयक्तिक और सांस्थानिक दोनों स्तरों पर लागू होने वाली कार्य-संस्कृति है। सत्र अध्यक्ष डॉ. नंद सिंह नरूका ने इस अवसर पर कहा कि शिक्षक के रूप में जो भी कार्य हमें आवंटित हैं उसको पूरी प्रतिबद्धता से पूरा करें तभी हम हमारी कार्य-संस्कृति की बात कर सकेंगे। समारोप सत्र के अवसर पर संबोधित करते हुए प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा, कुलपति पेसेफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर ने कहा कि आज हमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दो प्रकार की नैतिकताओं का प्रतिरक्षण करना होगा। पहला यह कि विद्यार्थी के विचार और व्यवहार को कैसे नैतिक बनाया जाए तथा दूसरा शिक्षक अपने ज्ञानार्जन से लेकर मूल्यांकन शोध और अध्यापन में श्रेष्ठता कैसे स्थापित करें। सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री महेन्द्र कपूर ने की। आभार डॉ. ग्यारसी लाल जाट, सचिव, शैक्षिक मंथन संस्थान ने ज्ञापित किया। सत्र संचालन डॉ. ओम प्रकाश पारीक ने किया। संगोष्ठी के आयोजन में संगठन के कार्यकर्ताओं की प्रमुख भूमिका रही। संगोष्ठी में रुक्टा (राष्ट्रीय) के 80 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

6. **राष्ट्रीय मीडिया कार्यशाला में सहभाग** - 6 मई 2018 को भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मीडिया कार्यशाला में रुक्टा (राष्ट्रीय) के कार्यकर्ताओं ने सक्रिय सहभाग किया। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मुख्य वक्तव्य देते हुए प्रो. राकेश सिन्हा ने आचार्य कृपलानी व काका कालेलकर के आदर्शों के अनुसरण की आवश्यकता जताई। उन्होंने समाज के व्यापक हित से समाचार को जोड़ने की बात कही। कार्यशाला में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष प्रो. जे. पी. सिंघल ने संगठन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री महेन्द्र कपूर ने चरित्र एवं आंतरिक दृढता को समाज की सुस्थिति निर्माण हेतु आवश्यक बताया।

अगले सत्र में लोकसभा टेलीविजन के सम्पादक श्री श्याम किशोर ने प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया के महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए अपने विचारों के व्यवस्थित प्रकटीकरण करने हेतु कहा। 'सोशल मीडिया एवं इसके लाभ' विषय पर आयोजित सत्र में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट शिल्पी तिवारी व सुरेन्द्र चतुर्वेदी ने अपने अनुभव साझा किए। समारोप सत्र के मुख्य वक्ता इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के निदेशक श्री रामबहादुर राय रहे। इसके अतिरिक्त विभिन्न सत्रों में भारतीय जनसंचार संस्थान के निदेशक श्री के. जी. सुरेश, राष्ट्रीय महामंत्री श्री शिवानंद सिंदनकेरा एवं स्वदेशी विद्यालय के फाऊण्डर संदीपसिंह ने विषय रखे। रुक्टा (राष्ट्रीय) की ओर से डॉ. अनिल दाधीच, डॉ. विवेक मण्डोत, डॉ. सुरेन्द्र सोनी, डॉ. योगेश गुप्ता, डॉ. भंवरसिंह राठौड़ एवं डॉ. मुकेश शर्मा ने कार्यशाला में सक्रिय सहभाग किया।

7. **पर्यावरण एवं स्वास्थ्य जागरूकता हेतु साईकल रैली** - संगठन की अजमेर इकाई द्वारा एक साईकल रैली का आयोजन 13 जून 2018 को प्रात: किया गया। जिसमें 70 शिक्षकों ने भाग लिया। रैली के समापन के बाद एक बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सह संगठन मंत्री डॉ सुशील बिस्सू ने अपने उद्‌बोधन में बदलते परिवेश के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे विपरीत प्रभावों पर घोर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस वर्ष इतनी भीषण गर्मी पड़ी है कि सिंचन के बावजूद हजारों पेड़ जल गए। इस हेतु विशेष प्रयत्न करने आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक छायादार वृक्ष न केवल लगाए, बल्कि उसकी पूरी सार सम्भाल करे, साथ ही अपने जन्मदिन के साथ स्वयं द्वारा लगाए वृक्ष का भी जन्मदिन समारोहपूर्वक मनाए। आज पर्यावरण की जो नेमत हमें मिली है, वह हमारे पूर्वजों की सूझबूझ और श्रम का परिणाम है। साथ ही, उन्होंने उपस्थित शिक्षकों और विद्यार्थियों से आह्‌वान किया कि सप्ताह में एक दिन ईंधन की बचत के साथ-साथ पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 'नो व्हीकल डे' रखना चाहिए। प्रयास यह हो कि सभी साईकल पर महाविद्यालय आएं। यदि अधिक दूरी पर रहते हों, तो कम से कम व्हीकल पूल करके आएं या सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। अंत में इकाई सचिव डॉ एल. डी. सोनी एवं साईकल रैली आयोजन सचिव डॉ अनूप आत्रेय ने सभी का आभार जताया।

8. **महापुरुषों की जयंती कार्यक्रम** - सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता डॉ. गीता शिवनानी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन, व्यक्तित्व व कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। डॉ लता अग्रवाल ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को एक अत्यंत उदार सम्राट बताते हुए कहा कि उन्होंने अनेक बार हराने के बाद भी शत्रु को जीवित छोड़ दिया, जो अंतत: घातक सिद्ध हुआ। उपाचार्य डॉ हासो दादलानी ने भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन के प्रेरक प्रसंग अपने व्याख्यान में सुनाए तथा संगठन को ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की बधाई दी। अध्यक्षीय उद्‌बोधन में उपाचार्य डॉ. पी. सी. सेठी ने कहा कि रुक्टा (राष्ट्रीय) ऐसे महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित कर अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता भी प्रकट करता है, जो प्रशंसनीय है।कार्यक्रम का संचालन इकाई सचिव डॉ लीलाधर सोनी ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्राध्यापक एवं महाविद्यालय के विद्यार्थी उपस्थित रहे। इसी प्रकार महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर संगठन की अजमेर इकाई के कार्यकर्ताओं ने राजकीय महाविद्यालय अजमेर में अवस्थित महाराणा प्रताप की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उनकी व्यक्तित्व एवं कृतित्व का स्मरण किया तथा राष्ट्रहित में कार्य करने का संकल्प लिया।

9. **एक शिक्षक-एक वृक्ष अभियान** - धारणक्षम जीवन एवं पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्य बोध को दृष्टिगत रखते हुए पिछले वर्ष से रुक्टा (राष्ट्रीय) ने ''एक शिक्षक-एक वृक्ष'' अभियान हाथ में लिया है। पिछले वर्ष आप सभी शिक्षक साथियों के सहयोग एवं कार्यकर्ताओं के प्रयासों के चलते कुल 4566 पौधे एवं वृक्ष रोपे गए। यह कार्यक्रम

मात्र पौधारोपण तक ही सीमित नहीं वरन् उसके संरक्षण व पालन की भी जिम्मेदारी हम लें, यह ''एक शिक्षक-एक वृक्ष'' अभियान का हेतु है। कई स्थानों पर पिछले वर्ष लगाए गए वृक्षों के जन्म दिवस मनाने के उत्साहजनक समाचार है। इस दिशा में अभी भी गंभीरता में काफी कार्य किया जाना शेष है। पर्यावरण संरक्षण; सिद्धान्त से ज्यादा व्यवहार का विषय है, अत: आप सभी शिक्षक साथियों से प्रतिवर्ष एक वृक्ष लगाकर उसके लालन-पालन के संकल्प लेने का विनम्र निवेदन है। इस अभियान की सफलता आने वाली पीढ़ियों के लिए हम शिक्षकों की ओर से एक अनुपम उपहार होगा।

10. **सदस्यता अभियान सम्पन्न** - संगठन का वार्षिक सदस्यता अभियान प्रदेश कार्यकारिणी के निर्णयानुसार 2 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक सम्पन्न किया गया। सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं के प्रयासों एवं आप सब शिक्षक साथियों के सहयोग से सत्र के प्रथम दिवस को ही 3713 शिक्षकों की सदस्यता प्राप्त हुई। भौगोलिक दृष्टि से क्षैतिजत: सभी शिक्षक साथियों द्वारा सदस्यता अभियान को भरपूर सहयोग एवं समर्थन देने के उत्साहजनक समाचार है। संगठन पर अपना स्नेह एवं विश्वास बनाए रखने के लिए संगठन धन्यवाद देते हुए आप सभी की भावनाओं के अनुरूप व्यापक शिक्षा एवं शिक्षकहित में निरन्तर कर्मरत रहने का संकल्प व्यक्त करता है। सदस्यता का विस्तृत विवरण अगले परिपत्र में दिया जाएगा।

    प्रदेश भर में संगठन की योजनानुसार इकाईश: गुरुवंदन कार्यक्रम उत्तम संख्या में सम्पन्न हुए हैं। एक शिक्षक-एक वृक्ष अभियान में भी शिक्षकों का अच्छा सहभाग मिला है। इनकी विस्तृत जानकारी अगले परिपत्र में प्रस्तुत करेंगे। आने वाले दिनों में हम विभागश: कार्यक्रम व विश्वविद्यालय सम्मेलन सम्पन्न करने वाले हैं। इनमें आपसे सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह है।

स्वतंत्रता दिवस, रक्षा बंधन एवं जन्माष्टमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।

भवदीय

(डॉ. नारायणलाल गुप्ता)
[महामंत्री]

20, चित्रकूट कॉलोनी,
माकड़वाली रोड़, अजमेर-305004

अमृत वचन

''किसी विषय-विशेष में मानव-जाति ने अब तक जो कुछ उपलब्धि प्राप्त की है, गुरु अपने शिष्य को उससे अवगत कराते हुए उसे अद्यावत् बना देता है। जिस प्रकार अपने माता-पिता से हमें अपना भौतिक शरीर प्राप्त होता है, वैसे ही गुरु के माध्यम से हमें बौद्धिक एवं आध्यात्मिक जीवन प्राप्त होता है। गुरु को उसके जीवन में जितना भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसे वह अपने शिष्य पर उद्घाटित कर देता है। इसलिए गुरु का सर्वप्रथम आवश्यक गुण, प्रधान योग्यता यह है कि उसमें अध्ययन की असामान्य शक्ति होनी चाहिए। अपने ज्ञान को सतत परिमार्जित करते हुए उसे अद्यावत् रखना चाहिए।''

- भगिनी निवेदिता

उच्च शिक्षा संस्थानों की परिसर संस्कृति सुधार हेतु आह्वान

अपने विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय परिसरों में हम सब शिक्षक साथी जीवन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा गुजारते हैं। हमारे विद्यार्थी एवं संस्थान परिसर मात्र हमारे जीविकोपार्जन से ही संबंधित नहीं है, वरन् जीवन के उद्देश्य एवं संतुष्टि की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। अपने परिसरों का भौतिक स्वरूप एवं शैक्षणिक वातावरण उत्तरोत्तर रूप से सुधार एवं विकास की ओर अग्रसर हो, इसमें दो राय शायद ही कोई शिक्षक साथी रखता हो, कई शिक्षक साथियों ने स्वप्रेरणा से इस दिशा में सार्थक कर भी दिखाया है। किन्तु अभी भी बड़ी मात्रा में प्रयत्नों की जरूरत है। यह सही है कि परिसर संस्कृति सुधार एवं विकास समग्र रूप से सरकार, विद्यार्थी, अभिभावक व शिक्षक के सामूहिक प्रयत्नों से ही हो सकता है, किन्तु शिक्षक इन सब में सबसे प्रमुख भूमिका निभाने में सक्षम है। आप सब शिक्षक साथियों से समय-समय पर चर्चा के दौरान इस पीड़ा का अभिव्यक्तीकरण हुआ है। ''शिक्षा के हित में शिक्षक'' यह ध्येय वाक्य सदैव संगठन की कार्यपद्धति का हिस्सा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए संगठन आप सबसे अपने-अपने स्थान पर परिसर संस्कृति सुधार हेतु व्यक्तिगत एवं सामूहिक योगदान कर बेहतर शैक्षणिक वातावरण बनाने में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान करता है। इस हेतु कतिपय करणीय बिन्दु निम्न हो सकते हैं -

1. विद्यार्थी हमारी पूंजी है। उनसे हमारा अनौपचारिक संवाद बढ़ना चाहिए। परिसर संस्कृति में सुधार, बिना छात्रों को साथ लिए करना मुश्किल है।
2. वर्ष में न्यूनतम एक बार हम अभिभावक संवाद कार्यक्रम रख सकते हैं। इसे विद्यार्थियों की सही स्थिति जानने में दो तरफा स्पष्टता होगी।
3. जनसहयोग/राजकीय मद/स्वयं प्रेरणा से परिसर में जगह-जगह कचरा पात्र लगे तथा कचरा इन पात्रों में डालने हेतु जागरूकता अभियान चले तो अति उत्तम रहेगा।
4. अपने शिक्षण-परिसर प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनें। चाय आदि कांच/चीनी के कप/गिलास में वितरित हो तो बहुत अच्छा रहेगा।
5. विद्यार्थी संगठनों को विश्वास में लेकर परिसर की दीवारों, गेट आदि पर पोस्टर, नारा लेखन प्रतिबंधित कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ही पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया जाए।
6. अपने परिसर में जल संरक्षण, सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन जैसे प्रकल्पों को बढ़ावा मिलना चाहिए। कुछ महाविद्यालयों ने इस संबंध में उत्तम कार्य किये हैं।
7. 'एक शिक्षक-एक वृक्ष' जैसे अभियान से लेकर 'एक छात्र-एक वृक्ष' अभियान तक एवं आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लेते हुए क्या हम व्यावहारिक धारणक्षम जीवन को दर्शाता हुआ हरा-भरा परिसर बना सकते हैं?
8. हम सभी शिक्षक व विद्यार्थी सप्ताह/पखवाड़े में एक दिन सार्वजनिक वाहन या साइकिल से आना तय कर सकते हैं क्या? या कि प्रतिदिन अपना वाहन पूल करके आ सकते है?
9. पुस्तकालय, खेल मैदान, नवीनतम शिक्षण विधियाँ, छात्र सहायता प्रकल्प आदि कई विषय परिसर संस्कृति से जुड़े हैं, जिनमें हम नवाचार कर सकते हैं।

ये सब बातें, इन कटु वास्तविकताओं के साथ है कि - शैक्षणिक व अशैक्षणिक कर्मियों की कमी है; राजनीति के लिए शिक्षा प्राथमिकता का विषय नहीं है; राजकीय सहायता अपर्याप्त है और गैर शैक्षणिक कार्य बढ़े हैं। इन सब सीमाओं के बाद भी कई शिक्षक साथियों ने व्यक्तिगत एवं सामूहिक संकल्प शक्ति के अनूठे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। संगठन समस्याओं के समाधान, शिक्षक अधिकार व सुविधाओं हेतु निरंतर प्रयासरत है, किन्तु अपने पक्ष की जिम्मेदारी हम भली-भाँति निभाकर समाज में उत्तम उदाहरण प्रस्तुत कर सकें, इस हेतु भी आप सबसे उपर्युक्त आह्वान है। अपने भौतिक - मानवीय संसाधनों की सीमा-क्षमता के अनुरूप उपर्युक्त बिन्दुओं में से अधिक से अधिक बातों पर व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से कार्य करने की आप सब शिक्षक साथियों से प्रार्थना है।